committee in which the Ministry of Railways is represented, Railway Board is represented, the Ministry of Industries is represented, fixes the cost. If they want to change the cost, they are at liberty to change the cost. So, on what consideration from the last year onwards, the rolling stock requirement policy has been changed by the Ministry of Railways?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, please बैठ जाइये।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: And what about the Ministry of Industry's letter of the 30th June, 1993, wherein she has told the same thing what I am repeating here? Is the Government running in the same manner? I do not understand it. ...(*Interruption*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF: It is a speech and not a question. How can I answer it? ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the question?

SHRI MD. SALIM: Madam, he has asked a very specific question. The Cabinet decision was taken in 1974 and in 1981 when Shrimati Indira Gandhi the respected leader of the nation, was the Prime Minister. Why has that decision been changed now? ...(*Interruption*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI C.K. JAFFER SHARIFE: Madam, when the budgetary support has gone down, naturally, any Ministry will have to do some exercise to find out how to save money and from where to get money. This is one of the processes. ...(*Interruption*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF. The question is how we will able to save money. I have given you only one example. Out of the total requirement, it is only ten per cent which we gave to the private sector through an open tender and we got Rs. 3 crores. Now, the present indication is that we are going to save Rs. 18 crores. It is entirely for the House; you are the trustees of the public exchequer. You must take a decision. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen to him. I want complete silence.

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF: Madam, I have very clearly quoted the very guidelines of the Ministry of Industry. But the hon. Member was trying to tell something else. This suits them. This is what I have to follow.

Adjustment of Unused Calls

†*682. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mahanagar Telephone Nigam Limited recovers the amount of call charges beyond bi-monthly 150 free calls;

(b) if so, whether MTNL would consider to adjust the amount of call charges lesser than 150 bi-monthly, in the rental of the subscribers;

(c) whether the Minister or the MTNL have received several representations for adjusting the amount of unused calls in the rental or to give due credit to the subscribers;

(d) if so, what are the details thereof and the action taken thereon;

(e) whether Government would consider to carry over the unused calls to the next bi-monthly bill, and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir

(b) No, Sir.

(c) and (d) A few representations had been received These were examined. It is not considered possible to accept this demand.

(e) No, Sir.

(f) The tariff had been determined after a careful consideration of fixed and variable costs of the network. Moreover, issues of tariff will now need to be considered by the Telecom Regulatory Authority of India.

†The Question was actually asked in the floor of the House by Shremati Malti sharma.

श्रीमती मालती शर्मा: उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वे कौन सी कठिनाइयां हैं, जो यह फ्री काल मिलती है जो उपभोक्ता की बच जाती हैं, वह उसके अगले खाते में जमा नहीं हो सकतीं? महोदया, मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं। मेरी जानकारी में है कि मुजफ्फरपुर में एक कस्बा चरथावल है जिसके टेलीफोन पूरा महीना खराब रहे। और टेलीफोन के बिल बाकायदा पूरे पूरे आते हैं। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह टेलीफोन विभाग की तरफ से जो लापरवाही है और उपभोक्ताओं को उसका भुगतान करना पड़ता है माननीय मंत्री जी इसके संबंध में क्या करेंगे? क्या वे उपभोक्ताओं को कुछ छूट देंगे? आपकी ही नाक के नीचे यहां चाणक्यापुरी टेलीफोन एक्सचेंज की हालत खराब है। वहां पता ही नहीं चलता, अक्सर टेलीफोन खराब रहते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, वे अपनी काल पूरी नहीं कर पाते हैं तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या अपने विभाग को ठीक करने का कष्ट करेंगे और जो इस प्रकार से टेलीफोन खराब रहते हैं उनके ऊपर अनाप शनाप बिल आते हैं इस सब की जांच कराने का मंत्री जी कष्ट करेंगे।

श्री सुख राम: मैडम, फ्री काल का जो कन्सेप्ट है यह तब इंट्रोड्यूस हुआ था जबकि अभी टेली कम्युनिकेशन को लग्जरी समझा जाता था ताकि हम उपभोक्ताओं को इंसेंटिव दें कि वे ज्यादा टेलीफोन का इस्तेमाल करें। मगर आज दूसरी स्टेज आ गयी है। यह 275 से शुरू हुआ था। बाई मंथली 275 फ्री काल्स थीं। मगर इनको आहिस्ते आहिस्ते कम किया गया क्योंकि आज टेली कम्युनिकेशन जो है वह हर परिवार के लिए नेसेसिटी है चाहे वह अमीर है या गरीब है। इस वास्ते अगर आपको ख्याल होगा जब मैंने इसका रिविजन किया था तो उस मौके पर 120 इसको रिड्यूस किया था मगर माननीय सदस्यों ने मांग की कि इसको 150 ही रहने दिया जाए तो मैंने आपके सुझाव को माना और 150 ही रखे। जो हमने एक स्टडी कंडक्ट करायी उसके माध्यम से पता लगा कि 15 प्रतिशत ऐसे लोग हैं सारे देश मे जिनकी जो डेढ़ सौ काल्स दो महीने की हैं उनका वे इस्तेमाल नहीं करते। उनको आगे ले जाने में बहुत सी परेशानियां आएंगी इस वास्ते यह मुमकिन नहीं है। यह सुविधा जो दी गयी है उसका वे इस्तेमाल करें यह उनके ऊपर है। अभी आपने जिक्र किया कि 2-4 जगह टेलीफोन खराब रहते हैं। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्या ने जो कहा वह ठीक होगा। मैं उस पर डिस्प्यूट नहीं करता। । करोड़ 24 लाख टेलीफोन्स की कैपेसिटी हमने क्रीएट की है उसमें 98 लाख टेलीफोन देश में लगे हैं। मैं मान सकता हूं कि कहीं कहीं खराबियां होंगी। उन खराबियों का दूर करना हमारा फर्ज बनता है। माननीय सदस्या जब भी बताएंगी कहीं टेलीफोन की खराबी है तो हम उसको दूर करेंगे। जो आपने बिल के बारे में कहा... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: आपका अपना ही टेलीफोन खराब रहता है।

श्री सुख राम: आपको तो सांत्वना होनी चाहिए कम से कम मंत्री का टेलीफोन भी... (**व्यवधान**) खराब रहता है।

जहां तक ओवर बिलिंग का आपने मसला उठाया, 4 करोड़ बिल्स एक वर्ष में इश्यू होते हैं और इन 4 करोड़ बिल्स में जहां 1992-93 में 2,48,248 ओवर बिलिंग के केसेज थे 1994-95 में 1,73,335 हो गए। इसमें प्रतिशत में अगर देखें तो 0.74 प्रतिशत...

उपसभापति: मंत्री जी सवाल के मुताबिक जवाब दीजिए। मेरे पास टाइम कम है।

श्री सुख राम: अब उन्होंने प्रश्न तो सारे पूछ लिए। उनका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा।

श्रीमती मालती शर्मा: टू इ प्वाइंट मैं यह जानकारी चाहती हूं कि जिस तरह से फोन खराब रहते हैं लेकिन बिल फिर भी आ जाते हैं तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर उन उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे?

श्री सुख राम: जरूर जांच कराऊंगा अगर आप मेरी नोटिस में ऐसे केसेज लाएंगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, it is a fact that telephone is a health hazard now because, first, we get wrong numbers Second, there are no basic amenities and facilities provided to the consumers. The consumers have to register themselves with a heavy deposit and wait endlessly for a telephone connection. After all, this is just a simple facility In other countries, the more you use the telephone, the less cost you pay so that it becomes user-friendly. People use it as a basic necessity. It is no longer a luxury to have a telephone today.

हमारे यहां की टेलीफोन काम नहीं करती है, मगर लाइनमैन

I would like to know: What action is the Department taking against these linemen who misuse the telephones of the other people, particularly, the telephones of Members of Parliment? Madam, I am tired of people saying that we get free telephone. Newspapers write columns that we get free telephone.

हर आदमी हमारे यहां आकर लाइन लगा लेता है और इनको एक-एक टेलीफोन लाइनमैन दूसरों को 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार रुपये में महीने को देते हैं, दे टेक ए कान्ट्रैक्ट और लगाओ द लाइन्स।

Right from the J.E. (Telephones) to the people downward, there is a network and this was exposed. (*Interruptions*) There is an additional injury, Madam. It is compounding the injury. We get inflated bills. When we question it... तो वह बालेते हैं कि

पहले आप पैसे लाकर जमा कर दीजिए, नहीं तो हम कनैक्शन काट देंगे।

Madam, this is, absolutely, proving to be a health hazard. It is contributing to our ill-health. Our blood pressure goes up. We get heart attack. This is also a security hazard. आप किसी से बात करें सारा दिल्ली शहर हमारा टेलीफोन सुन रही है। या तो हम दिल्ली पुलिस का लाइन हमारे इस पर आ जाती है .....(व्यवधान) हां, हम पूरा सुन चुके हैं, कैबिनेट का भी हम काफी सुन चुके हैं। ...(व्यवधान)

This is what is going on. (*Interruptions*)

उनका एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा। ....(व्यवधान)

This problem is there only in India. The more you use the telephone, the more it costs the consumer. This is a consumer item. We deposit money. We pay interest-free money. They use it happily. The Department uses it. On top of it, they overbill you for the services not rendered to the consumer! They are taking money from the people.

जो बेवकूफ बन कर दाखिल करके आते हैं और फिर उसके बाद उनको कोई नो होप, कोई उम्मीद ही नहीं है।

People like us are suffering. As I said, there is a whole network of crime going on. Therefore, may I know from the hon. Minister what action he is taking?

एक और भी है मैडम, यह लोग टेलीफोन बिल्डिंग्ज किराए पर ले लेते हैं और फिर उन को खाली नहीं करते हैं।

They are paying 1954 rents to the owners of these buildings.

मैंने मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। ...(व्यवधान)

SHRI P. UPENDRA: There should be a general review, Madam. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There should be a discussion, half-an-hour discussion. (*Interruptions*)

SHRI SUKH RAM: This was short of a speech. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: It is not a speech. It is an appeal. (*Interruptions*) I am pleading with you. (*Interruptions*) I have a dispute with your Department.

SHRI SUKH RAM: Let me reply to the points which you have raised. (*Interruptions*) Madam, she says that telephone is a health hazard and that it causes blood pressure, heart attack and other things. If that is so, I fail to understand why there is a waiting list of about two million; why so many people should be waiting to get a telephone. (*Interruptions*) There may be a few cases where subscribers might have faced certain problems of overbilling, or their telephones not being in order. (*Interruptions*)

I would like to point out, Madam that during the Eighth Five-Year Plan, we have installed more than four million telephones in the country. This is equal to the total number of telephones installed in the last seven five-year plans. During the next two years, we are likely to achieve about four million.

As far as the capacity is concerned, as I said earlier, it is about one crore and twenty-five lakhs. Out of this, we have given about ninty-eight... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: She is not asking about that.

SHRI DIGVIAJY SINGH: She had asked something and you are telling something else. (*Interruptions*)

SHRI SUKH RAM: As I said there may be certain problems of overbilling. In certain cases, the telephones may not be in order.

Consumers are facing this problem. We have taken some steps.

श्रीमती रेणुका चौधरी: नहीं-नहीं मंत्रीजी, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि-

There is a network of Linemen who are giving connections to other people who pay at flat rates. Those calls are being made. It was discovered even in Connaught Place I have raised it in the House. ...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute. Let him answer.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He is not answering.

SHRI SUKH RAM: Complaints against Linemen and officers also have been received. Wherever complaints have come to our notice we have taken action. (*Interruptions*)

SHRI DIGVIJAY SINGH: What kind of action have you taken?

SHRI SUKH RAM: Some Linemen have been suspended

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. ...(*Interruptions*)

SHRI SUKH RAM: Some officials have been suspended. Action has been taken. This is what we could do.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: जब आधा-आधा घंटे की फॉरेन कॉल होती है कहीं-न-कहीं तो वह पड़ती है?

मैंडम, सौ-सौ रुपए में ऐसे कॉल्स होते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: कितने लोगों को आपने जेल भेजा है ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKH RAM: The law does not provide for that. We are now bringing in an amendment to the Indian Telegraphs Act, in which there will be a provision for imprisonment ...(*Interruptions*)

The law did not provide for it so far.

SHRI DIGVIJAY SINGH: There is the criminal law.

शाउट न करें तो क्या करें? आप लोग तो मंत्री हैं, लेकिन हम लोग तो गरीब मेंबर हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please. Please. ....(*Interruptions*)

SHRI B.V. ABDULLA KOYA: I have been charged Rs. 24,000/-.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He has been charged Rs. 24,000/-! This is scandalous.

SHRI B.V. ABDULLA KOYA:I have written a letter to the Minister also. .(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. One minute. Just one minute.

श्री दिग्विजय सिंह: मैडम, एक माननीय सदस्य के साथ अगर ऐसा होता है, तो किस की गवाही की जरूरत है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: मंत्रीजी, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप लोगों को टेलीफोन लाइंस कनेक्ट कर के दे देते है। सब लोगों की ग्रीवेंस यह है कि आप लाइन दे देते हैं, नए टेलीफोन दे देते हैं और वह टेलीफोन जिन को दिए जाते हैं, दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं और बिल उन को भरना पड़ता है। उस कनेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... एक मिनिट अंसारी जी बैठिए। प्लीज, आप चुपचाप बैठिए। देखिए मंत्रीजी, एक एम०पी० आपके सामने बोले कि वह यहां रहते नहीं हैं। मैं विटनेस हूं क्योंकि ये कभी-कभी हाउस में आते हैं। उनका अगर 24 हजार का बिल आएगा तो कोई फरिश्ते तो यूज नहीं कर रहे हैं उनका टेलिफोन? कोई मिसयूज कर ही रहा है... (**व्यवधान**)... अगर आप लोग अपना एक मिनिट मुंह बंद रखें तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूं वरना आप खुद ही हैंडल कर लीजिए और क्वैश्चंस मत पूछिए हाउस में? मंत्रीजी इस बारे में आप कुछ निर्णय लीजिए क्योंकि यह तो क्रिमिनल ऑफेंस है और आप को कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुख राम: मैडम, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे केसेज हैं जहांकि ओवर-बिलिंग के केसेज भी आते हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: बैठिए, उन्हें बोलने दीजिए। मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

श्री सुख राम: उसमें हम ने चारों मेट्रोपोलिटन सिटीज में सी०बी०आई० के सेल बना दिए हैं और अगर कोई ऐसा केस हो जहां कि टेलिफोन का मिसयूज हो, तो वह सामने लाएं। उसमें कई केसेज पकड़े गए हैं जिन में कि सजा भी दी गयी है, कोर्ट में भी केसेज गए हुए हैं ..(**व्यवधान**)...

उपसभापति: पहले सुन लीजिए।

श्री सुख राम: अब इस में जहां तक हमारे एम्प्लाईज हैं, एम्प्लाईज को इम्प्रिजनमैंट के लिए जो हमारा इंडियन टेलिग्राफएक्ट है, उसमें प्रोविजन नहीं है। हम उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं और इस अमेंडमेंट में ...(**व्यवधान**)...हम ने सर्विसेज टर्मिनेट की हैं, हम ने उन को सस्पेंड किया है।

मगर इम्प्रिजनमेंट वह तो आप जानते है सारा क्योंकि उसमें पुलिस में ....(**व्यवधान**).... हमारे पास सी॰बी॰आई॰ का सेल है, मगर they do not enjoy the powers.

श्री दिग्विजय सिंह: यह एम॰पी॰ कह रहे हैं, इनकी चिट्ठी है आपके पास, आपने जवाब क्या दिया? .... (**व्यवधान**).... कितने शरीफ आदमी हैं। आपने इनको क्या जवाब दिया है? क्यों इनसे पैसा लिया? .... (**व्यवधान**)...

श्री सुख राम: आप प्रश्न उठाइए उसके बारे में। .... (**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour is over. (*Interruptions*) Order, please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, he cannot be saved by the bell. This is a serious thing. There is a terrible harassment.

उपसभापति: आप मंत्री जी से बाहर मिलिएगा। ... (**व्यवधान**)... क्वैश्चन आवर ओवर हो गया। आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप अपनी जगह पर जाइए। ... (**व्यवधान**)...

It is a real chaos. This is not the way. Still the House is in order. You cannot come and lobby here. You go and talk to him in the lobby.

मंत्री जी, मुझे अफसोस इसका है और खतरा कि जिन लोगों ने यहां बात उठाई है, कल उनका टेलीफोन कहीं कोई गलती से काट न दे। ...(**व्यवधान**)... They may take this type of revenge. I am a victim of it: It happened to me in Bombay. Even though I am Deputy Chairman, it did happen to me. (*Interruptions*) Now, papers to be laid on the Table. Shri Kamal Nath.

SHRI SUKH RAM: Madam, I will take just one minute. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. Because it hurts people, let him say. I wanted him to say something because it concerns the citizens and the privileged citizens, which you people are supposed to be. Everybody thinks so. But it happens. People are worried.

This is a problem, Mantri Ji. You do not know that the people are suffering. You may also know about it, but you have not been able to help. We will help you to see how Parliament can strengthen your hands.

श्री सुख राम: मैंने माननीय सदन के तीन मैम्बर आफ पार्लियामैंट की कमेटी बनाई, जिसमें दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से मैम्बर रखे। ...(**व्यवधान**)...मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कमेटी बनाई और जितने मैम्बर्स आफपार्लियामैंट की ओवर-बिलिंग के प्रश्न हैं सारे, उनसे मैंने कहा कि आप कोई रिकमंडेशन, कुछ सुझाव मुझको दीजिए, जिससे कि एक रास्ता निकले, मगर उस कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: Not a single Member of Parliament has been informed about this Committee. किसी को कोई इंफैरमेशन नहीं है इस कमेटी के बारे में।

श्री दिग्विजय सिंह: कहां कमेटी बनाई है? मैडम, यह हर बार गलत बात करके चले जाते हैं सदन से।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, every MP is a victim of the Telephone Department. (*Interruptions*)

SHRI DIGVIJAY SINGH: He does not reply to the letters written by the MPs. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: You have to hear the grievances of the public. (*Interruptions*) Madam, I have written so many letters to him.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I can show you the bunch of letters written by MPs.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Even acknowledgement is not sent by the Minister to the Members of Parliament.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will discuss it. We will have Half-an-Hour Discussion. We will request the Chairman to give his permission. We will discuss with the Minister. Now, let us go ahead with the "List of Business".

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, हुआ क्या? आपने मेहरबानी से यह कहा कि आपके ऐतराज़ के बाद मिनिस्टर साहब को मौका दिया जाए, मौका देने के बाद क्या कहा उन्होंने ?

†[श्री सिकन्दर बख्त: सर, साहब भूल गया। आपने मेहरबानी से यह कहा कि आपके एतराज के बजह मिनिस्टर साहब को मौका दिया जाए। मौका देने के बजह क्या कहा आपने।]

उपसभापति: कमेटी बनाई।

श्री सिकन्दर बख्त: कोई तरीका है यह कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियों के लिए कमेटियां मुकर्रर करते फिरें? लोगों को तकलीफ आज हो रही है, कौन कमेटी चाहिए? आपको अपने डिपार्टमेंट का कारोबार ठीक से चलाने की एहलियात होनी चाहिए।

†[श्री सिकन्दर बख्त: कोई तरीका है यह कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियों के लिए कमेटियां मुकर्रर करते फिरें लोगों को तकलीफ आज हो रही है-कौन कमेटी चाहिए-आप को अपने डिपार्टमेंट का कारोबार ठीक से चलाने की एहलियात होनी चाहिए।]

You must know how to make your Ministry work.

एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, कमेटी क्या करेगी? गलत बात है बिल्कुल, उसका जवाब आना चाहिए। ...(व्यवधान)... कमेटी क्या करेगी? ...(व्यवधान)...

†[एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कमेटी क्या करेगी-गलत बात है बिल्कुल-उसका जवाब आना चाहिए ... "मदाखलत" ... कमेटी क्या करेगी ... "मदाखलत" ...]

श्री रजनी रंजन साहू: मैडम, मेरा एक सवाल है।... (व्यवधान)...

उपसभापति: अभी सवाल-जवाब खत्म हो गए।... (व्यवधान)...

श्री रजनी रंजन साहू: मैडम, मेरा एक सवाल है कि इन्होंने कमेटी का कहा है ...(व्यवधान)...

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति: बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI SUKH RAM: Every is ..(*Interruptions*)... This was the suggestion made here in this very House ...(*Interruptions*)... I have constituted a committee. ..(*Interruptions*)... Let them go into it and give a recommendation. This was your suggestion, not my suggestion.

श्री सिकन्दर बख्त: यूज़लैस बात कर रहे है ... (व्यवधान)...

†[श्री सिकन्दर बख्त: यूज़लैस बात कर रहे हैं ... "मदाखलत" ...]

SHRI R.K. DHAWAN: Madam Deputy Chairman, I just want to bring an instance to the notice of the hon. Minister about overbilling in the month of November last year when I was operated upon and was lying in the All India Institute of Medical Sciences. I had a major operation. On that day when I was being operated upon, from my house telephone, seven international telephone calls were made and these calls have been shown against my telephone in the bill. I was in the hospital for seven days and during those seven days thirty-two telephone calls to a particular telephone were made and these were shown against my telephone in the bill. I have referred the bill to the Secretariat. They took up the matter.

A telephone was sanctioned in the month of January out of MPs quota to an officer. When that officer had been to the SDO, he said,

"एम.पीज. ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं"

They have made such a disparaging remark. Till today that telephone has not been installed. In this connection, I have written a letter to the hon. Minister. All the Members raising the point of overbilling is a very serious matter. I don't say it is the fault of the Minister, but there is something wrong with the official machinery and that machinery has to be moved and changed.

I would request the hon. Minister that he should listen to all the hon. Members, what they are saying and order an inquiry into these things and set things right.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI V. NARAYANASAMY: That is what we want ...*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing any more..

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, if these things are happening to Members of Parliament, you can imagine about an ordinary citizen.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already mentioned this point to the hon. Minister. Now the matter is closed. The Minister should find out and come to the House and tell us about what the hon. Members have raised here. मंत्री जी, आप पता लगाइए इसके बारे में और हाऊस में बता दीजिए। आप जिम्मेदार मंत्री हैं, आप इंकार नहीं करेंगे।

SHRI SUKH RAM: Madam, I should know the specific cases. I will definitely look into them.

SHRI R.K. DHAWAN: Just now I have brought a specific case to his notice.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: The Minister has given an assurance on the floor of the House that whenever a Member of Parliament recommends for a telephone connection it would be done within a month.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not bring those cases here. You can give the cases to him in the Lobby or in his office or wherever you like, but not here..

श्री रामजी लाल: मैडम, एक साल से मेरा टेलीफोन खराब है ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: एक साल से एम.पी. का टेलीफोन खराब है आम आदमी का क्या हाल होगा? ...(व्यवधान) ...

श्री रामजी लाल: 23 अगस्त को वह लगा था ... (व्यवधान)... उस दिन उन्होंने ...(व्यवधान)...आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: "राम जी" का टेलीफोन जब खराब है तो औरों का क्या हाल होगा? ... (व्यवधान)...

श्रीमती कमला सिन्हा: मैडम, टेलीफोन विभाग ... (व्यवधान)... टेलीफोन विभाग बहुत प्रदूषित हो गया है। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: बैठिए। बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... बैठिए अंसारी साहब, बैठिए। ...(व्यवधान)...

Sit down. Enough is enough.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

News reports about Delhi Police

*683. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items captioned, "Is Delhi Police Act violating Constitution" and "S.I., Panch consteblon ke Khilaaf mamla darj karne ke aadesh" appearing in the Hindustan Times and Dainik Jagran of 14th Februrary, 1995 respectively;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Metropolitan Magistrate, Delhi, made a reference in September 1990 u/s 395 Cr. PC in criminal case, State Vs. Mohd. Akram, to the High Court of Delhi for a decision on the question whether the provisions of Section 103 of the Delhi Police Act are violative of Article 20(3) of the Constitution of India. The Delhi High Court, in the above referred criminal reference No. 1/90, issued notices to the Standing Counsel and the Attorney General of India. A counter affidavit in opposition to the reference under consideration of the High Court of Delhi has been filed by the Delhi Government. The matter is subjudice before the Delhi High Court.

One Jitender Kumar, resident of Paharganj, accused in five different criminal cases registered in different police stations of Delhi, was arrested by Addl. SHO, Paharganj on 9.2.95. In the scuffle that occurred in the course of his arrest he suffered simple injuries on his person, which were confirmed when he was got medically examined at Lady Hardinge Medical Hospital, New Delhi. Jitender Kumar was produced in the court of Metropolitan Magistrate on 10.2.95 who discharged him and the Kalandra made u/s 41(1)(a) Cr. PC was dismissed. Jitender Kumar complained to the court that he was beaten up by the police. The court recorded the statement of Jitender Kumar u/s 164 Cr. PC and ordered registration of a